(घ) इस पर यदि कोई कार्रवाई की गई है तो वह क्या है और यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है और यह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 33 क और धारा 36 क के साथ पठित धारा 2 (आई), 2(ओ) में परिभाषित एकाधिकार, प्रतिबंधित और अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच कर सकता है और प्रविरत तथा प्रतिविरत" (सीज एंड डिजिस्ट) आदेशों को पारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग को अस्थाई व्यादेश देने और मुआवजा देने की शक्तियां भी प्राप्त हैं जहां किसी उपक्रम अथवा किसी व्यक्ति द्वारा किए गए एकाधिकारिक, प्रतिबंधित या अनुचित व्यापार प्रथाओं के फलस्वरूप, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी व्यापारी या व्यापारी वर्ग या किसी उपभोक्ता को कोई क्षति या नुकसान हुआ हो।

(ग) और (घ) औषध उद्योग में व्याप्त कतिपय अनुचित व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित एक शिकायत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में नवम्बर, 1991 में प्राप्त हुई थी। निदेशक (अनुसंधान), एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा शिकायत की प्रारम्भिक जांच की गई थी और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने (i) सिपला लिमिटेड, (ii) आई०पी०सी०ए० लेबोरेट्रीज लिमिटेड, (iii) रैन बैक्सी लेबोरेट्रीज लिमिटेड, (iv) स्टेनोल फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड, (v) कैडिला कैमिकल्स (पी) लिमिटेड, (vi) बिडल सायेर लिमिटेड, (vii) जगसोनपाल फार्मा लिमिटेड, (viii) एलाइड कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स (पी) लिमिटेड और (ix) फुलफोर्ड (इंडिया) लिमिटेड के मामले में मार्च, 1997 में एक प्रतिबंधित व्यापार प्रथा जांच (सं० 37/92) संस्थित की है। आयोग द्वारा मामले में 12.5.97 को सुनवाई की गई थी और अब यह 12.9.97 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है और यह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों के अंतर्गत इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिखायी गयी लाभांश की दर

4277. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कार्यरत शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिखाया गया लाभांश पिछले वर्षों के दौरान लगातार बढ़ता रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनके पूंजी निवेश के आधार पर 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान दिखाई गई लाभांश की दर कितनी रही है; और

(ग) उपर्युक्त लाभांश दर भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में औसत कितनी अधिक या कम है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) बहुराष्ट्रीय कंपनी की सामान्य रूप से स्वीकार्य परिभाषा नहीं है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ऐसा वर्गीकरण नहीं है। तदनुसार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तथाकथित वर्गीकरण पर आधारित देश में कार्यरत कंपनियों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

Passport issued in Tamilnadu

4278. SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of passports issued during 1996-97 by various Passport Offices in Tamil Nadu, district-wise;

(b) the steps being taken by Government to provide passports at the earliest to the applications of the State; and

(c) whether there is any proposal to open a Passport Office at Kanya Kumari District of the State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) A statement showing the number of passsports issued by Passport Office, Chennai and Passport Office, Tiruchirappalli in Tamil Nadu during the